International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.2 Nov-Dec 2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यावसायिक शिक्षा

डॉ. रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग,
शासकीय रणविजय प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया, म. प्र. भारत,
Corresponding Author – डॉ. रमेश प्रसाद कोल
Email- dr.rameshprasadkol@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.10560003

सारांश–
भारत में व्यावसायिक शिक्षा उन शैक्षिक कार्यक्रमों को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों को विशिष्ट करियर या कौशल के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से व्यावहारिक कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है जो सीधे कार्यस्थल पर लागू होते हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार अनौपचारिक क्षेत्र में एक कुशल श्रम शक्ति प्रदान करेगा जो औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादकता को और बढ़ाएगा। यूनेस्को की शिक्षा रिपोर्ट की नवीनतम स्थिति के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। भारत में व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिक लाभ छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, साथ ही उन्हें 21वीं सदी में आधुनिक कार्यस्थल की मांगों और चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है।

कीवर्ड– राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति 2020, व्यावसायिक

प्रस्तावना–

12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान था कि 19–24 आयु वर्ग (5 प्रतिशत से कम) में केवल भारतीय कार्यबल का बहुत कम प्रतिशत औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में यह संख्या सबसे अधिक है। जर्मनी में 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में यह 96 प्रतिशत है। ये संख्या केवल भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या के प्राथमिक कारणों में से एक तथ्य यह है कि व्यावसायिक शिक्षा अतीत में मुख्य रूप से ग्रेड 12–12 और ग्रेड ंदस और ऊपर की ओर छोड़ने वालों पर केंद्रित है। इसके अलावा, व्यावसायिक विषयों के साथ ग्रेड 12–12 पास करने वाले छात्रों के पास उच्च शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय के साथ जारी रखने के लिए अक्सर अच्छी तरह से परिभाषित मार्ग नहीं होते हैं। सामान्य उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी ऐसे छात्रों को खोलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे जिनके पास व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता थी, जो उन्हें अपने हमवतन के सापेक्ष 'मुख्यधारा' या 'अकादमिक' शिक्षा से वंचित कर रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा की धारा से छात्रों के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का पूर्ण अभाव पैदा कर दिया, एक मुद्दा जिसे केवल हाल ही में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की घोषणा के माध्यम से संबोधित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से हीन माना जाता है और इसका अर्थ बड़े पैमाने पर उन छात्रों के लिए होता है जो बाद में इसका सामना करने में असमर्थ होते हैं। यह एक धारणा है जो छात्रों द्वारा बनाए गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंता है कि भविष्य में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश कैसे की जाती है, इसकी पूरी पुनः कल्पना से ही निपटा जा सकता है।

इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम को दूर करना है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा के एकीकरण की आवश्यकता है। मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती उम्र में व्यावसायिक प्रदर्शन के साथ, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय सीखता है और कई और चीजों के संपर्क में है। इससे श्रम की गरिमा पर जोर दिया जाएगा और विभिन्न स्वरों, भारतीय कलाओं और कारीगरों को महत्व दिया जाएगा। 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। यह सतत विकास लक्ष्य 4.4 के साथ संरेखित है और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की पूर्ण क्षमता को महसूस करने में मदद करेगा। जीईआर के लक्ष्यों पर पहुंचने के दौरान व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों की संख्या पर विचार किया जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास वत अकादमिक 'या अन्य क्षमताओं के विकास के साथ–साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक प्रसाद में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए, माध्यमिक विद्यालय प्ज्, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ भी सहयोग करेंगे। एक हब और स्पोक मॉडल में स्कूलों में स्किल लैब भी स्थापित और बनाए जाएंगे जो अन्य स्कूलों को सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देगा। उच्च शिक्षा संस्थान अपने या उद्योग और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। 2013 में शुरू की गई डिग्री मौजूद रहेगी, लेकिन व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित

छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 4–वर्षीय बहु–विषयक स्नातक कार्यक्रम शामिल हैं। भ्म्प् को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न स्किल्स में शॉर्ट–टर्म सार्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। 'लोक विद्या', अर्थात, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। व्क्स् मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की संभावना का भी पता लगाया जाएगा। अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों को कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर चुना जाएगा। एमएचआरडी इस प्रयास की देखरेख के लिए उद्योग के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगी। व्यक्तिगत संस्थान जो शुरुआती दत्तक ग्रहण करते हैं, उन्हें काम करने वाले मॉडल और प्रथाओं को खोजने के लिए नवाचार करना चाहिए और फिर उन्हें NCIVE द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षुता के विभिन्न मॉडल, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग किए जाएंगे। उद्योगों के साथ साझेदारी में उच्च शिक्षा संस्थानों में ऊष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क प्रत्येक अनुशासन व्यवसाय और पेशे के लिए आगे विस्तृत होगा। इसके अलावा, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की मान्यता के लिए आधार प्रदान करेगा। इसके माध्यम से, फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ अपने व्यावहारिक अनुभव को संरेखित करके औपचारिक प्रणाली से ड्रॉपआउट को फिर से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट–आधारित फ्रेमवर्क भी श्सामान्यश और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेगा।

साहित्य समीक्षा

संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती है। पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र ''भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।'' "भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति पर बल देना है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से एक उत्पादक कार्यबल उत्पन्न करने के साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से युवाओं में स्व–रोजगार क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

वर्तमान में, केवल 7 से 10 प्रतिशत आबादी औपचारिक क्षेत्र में भाग लेती है, व्यावसायिक शिक्षा के विकास से अनौपचारिक क्षेत्र में एक प्रशिक्षित श्रम बल की पेशकश होगी, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) दोनों व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी में सुधार के महत्व के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर व्यावसायिक शिक्षा के लचीलेपन पर प्रकाश डालते हैं। भारत में शिक्षा।

एनकेसी ने नए वितरण मॉडल के माध्यम से क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ सार्वजनिक–निजी सहयोग बढ़ाने का भी सुझाव दिया। इसके आलोक में, सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक शिक्षा पर फिर से जोर दिया है। 2025 तक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्ब्) में सभी छात्रों के 50 प्रतिशत को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के विकास और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य के कुछ प्रमुख कारक नीचे दिए गए हैंरू शिक्षा का अधिकार अधिनियम किताबों और लिखित परीक्षाओं पर आधारित है। कुछ शोध–आधारित साक्ष्यों के अनुसार, बहुत से लोग 21वीं सदी के कौशल काम पर या उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीखते हैं जो क्षमताओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, व्यावसायिक शिक्षा की मांग है, जो विशेष कौशल सेट और सूचना प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में काम कर सकती है जिसे कार्यस्थल में लागू किया जा सकता है।

यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया–2020 के अनुसार, स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

यूनिसेफ 2019 के अध्ययन के अनुसार, कम से कम 47ः भारतीय युवा 2030 तक नौकरी के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने की गति से नहीं हैं। व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों को अक्सर विश्वविद्यालय के स्नातकों की तुलना में नौकरी पाने में कम समय लगता है। इसलिए, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति हाल के वर्षों में काफी विकास के साथ एक मिश्रित तस्वीर है लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं सामने हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की कुछ विशेषताएं हैं–अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों के व्यापक क्षेत्रों में दो साल की अवधि के 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले 9583 स्कूल हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) भी 80 पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन लगभग 6,00,000 है। कौशल भारत मिशन की शुरुआत 2015 में भारत को विश्व की ष्कौशल राजधानीष् के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति , जिसे 2015 में अद्यतन किया गया था, उच्च मानकों को बनाए रखते हुए तीव्र गति से कौशल विकास के मुद्दे को पहचानती है।

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के संशोधित व्यावसायीकरण के अनुसार, केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसमें ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शामिल होगी।

माध्यमिक शिक्षा के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राज्यों को प्रशासनिक ढांचे की स्थापना, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यचर्या तैयार करने, पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिका पाठ्यक्रम गाइड, प्रशिक्षण नियमावली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और विकास, प्रशिक्षण, और मूल्यांकन, और इसी तरह।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा के कुछ प्रमुख लक्ष्य

भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देना। देश के नागरिकों के आर्थिक स्तर में सुधार करना।

जनता को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर बेरोजगारी दूर करना।

मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

युवाओं को विशेषज्ञ तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करना।

सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रगति के लाभों के समान वितरण में योगदान देना।

आधुनिक विकास के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं को समझने में युवाओं की सहायता करना।

महिलाओं, ग्रामीण और आदिवासी छात्रों, और समाज के हाशिए के सदस्यों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के अवसर प्रदान करना।

व्यावसायिक शिक्षा के लाभ

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैंरू

व्यावहारिक कौशल: शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है जिसे सीधे उनके पेशेवर करियर में लागू किया जा सकता है। इससे छात्रों को अपने करियर में एक मजबूत नींव विकसित करने और उन्हें कुशल बनाने में मदद मिलती है। कैरियर की तैयारी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को विशिष्ट करियर या उद्योगों के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सहायता से छात्र विशिष्ट ज्ञान सीख सकते हैं और कौशल प्राप्त कर सकते हैं जो उनके चुने हुए पेशे के लिए प्रासंगिक हैं।

रोजगार सृजन: कई व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में एमएसएमई और बड़े उद्योगों के साथ मजबूत भागीदारी होती है, जो अक्सर स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों की ओर ले जाती है। इससे छात्रों को जल्दी रोजगार खोजने और बेरोजगारी को कम करने में मदद मिल सकती है।

लागत प्रभावी: पारंपरिक कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा अक्सर अधिक लागत प्रभावी होती है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अवधि में कम होते हैं और विशिष्ट कौशल और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

लचीला शिक्षण: व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन कक्षाओं सहित सीखने के लचीले विकल्प प्रदान करते हैं जो छात्रों के लिए अपनी शिक्षा का पीछा करते हुए काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना आसान बनाता है।

नए जमाने के करियर: कई व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम उच्च मांग और नए जमाने के करियर जैसे स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और कुशल व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन कार्यक्रमों के स्नातकों के पास अक्सर अच्छी नौकरी की संभावनाएं और कमाई की संभावना होती है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा के साथ चुनौतियाँ

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कई चुनौतियों का सामना करता है जो इसके विकास और विकास को प्रतिबंधित करता है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के साथ कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैंरू

संगठन और कमजोर कार्यान्वयन

भारत में व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की भारी कमी है। अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में उचित उपकरण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की कमी है। भारत में कई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खराब गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्नातकों में उनके चुने हुए पेशे के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी होती है।

सामाजिक कलंक

भारत में, पारंपरिक विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा को अभी भी निचले स्तर के शिक्षा विकल्प के रूप में देखा जाता है। नकारात्मक धारणा और सामाजिक कलंक के परिणामस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी हुई है।

लिंग भेद

भारत में व्यावसायिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण लिंग पूर्वाग्रह है, जिसमें कई पाठ्यक्रम लिंग–विशिष्ट हैं और महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करते हैं। धन की कमी और खराब **उद्योग लिंकेज**

भारत में व्यावसायिक शिक्षा अक्सर कम वित्तपोषित होती है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम विकास और संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण में निवेश की कमी होती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे स्नातक हैं जिनके पास व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभव की कमी है।

उभरती प्रौद्योगिकियों पर फोकस: भारत सरकार ने उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , ब्लॉकचौन और रोबोटिक्स के महत्व को पहचाना है और इन उभरते क्षेत्रों को पूरा करने वाले व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश कर रही है।

उद्योग–अकादमिक सहयोग: भारत में व्यावसायिक शिक्षा उद्योग और शिक्षा जगत के बीच अधिक सहयोग की संभावना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और शिक्षार्थियों को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान करना।

डिजिटल लर्निंग: COVID-19 महामारी ने व्यावसायिक शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को अपनाने में तेजी लाई है, और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। व्यावसायिक शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और

मिश्रित शिक्षण मॉडल के अधिक सामान्य होने की उम्मीद है।

उद्यमिता: भारत में व्यावसायिक शिक्षा द्वारा स्वरोजगार के लिए उद्यमशीलता और कौशल विकास पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना है। यह शिक्षार्थियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और दूसरों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

गुणवत्ता आश्वासन: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू कर रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम गुणवत्ता और प्रासंगिकता के आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।

निष्कर्ष–

निष्कषतः यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा में बुनियादी ज्ञान और मूल्य इस प्रकार शामिल होते हैं जिनमें विषय की मुख्य अवधारणायें, सिद्धांत और तकनीक के साथ साथ व्यवहार में उनके अनुप्रयोग का ज्ञान भी शामिल होता है, जैसे– चिकित्सा और कानूनी विषय द्य व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी क्षमता के ऐसे स्तर को ... उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शिक्षा, उद्योग–अकादमिक सहयोग और उद्यमिता पर अधिक ध्यान देने के साथ भारत में व्यावसायिक शिक्षा का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। स्किल इंडिया मिशन जैसी सरकार की पहल, निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के प्रयासों के साथ, एक मजबूत और गतिशील व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली बनाने की संभावना है जो शिक्षार्थियों, उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगी। मौजूदा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में चुनौतियों और कमियों को दूर करना भी आवश्यक है

संदर्भ

1. माइकल ए. वेन्स्टीन, व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत, (कोलंबस, ओहियोः चार्ल्स ई. मेरिल 1971),
2. माइकल ए. वेन्स्टीन, व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत, (कोलंबस, ओहियोः चार्ल्स ई. मेरिल 1971),
3. सीबी मैकफर्सन, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पी. 100, पारेख द्वारा उद्धृत, समकालीन राजनीतिक विचारक, लंदन, 1982।
4. वेंडी ब्राउन, एज वर्क: क्रिटिकल एसेज ऑन नॉलेज एंड पॉलिटिक्स, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005)।
5. भार्गव और आचार्य, राजनीतिक सिद्धांतः एक परिचय (नई दिल्लीः पियर्सन, 2008) में उद्धृत।
6. वैन ब्रैकेल, जे, 'प्राकृतिक प्रकार और जीवन के प्रकट रूप', डायलेक्टिका, संख्या 46 (1992) (पीपी. 243–259),